Shri N. S. Sharma:
Shri Sharda Nand:
Shri Brij Bhushan Lal:
Shri Atal Bihari Vajpayee:
Shri Ram Kishan Gupta:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to import more cotton to feed the textile mills now in crisis for want of raw material;

(b) if so, when a decision is likely to be taken; and

(c) the amount of cotton likely to be imported during the current year and at what price and from which countries it will be imported?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) to (c). Efforts are being made to import additional quantities of cotton. An agreement has already been entered into with the U.A.R. providing *inter alia* for import of about 200,000 bales of cotton. Other negotiations are in progress.

About 800,000 bales are likely to be imported from different countries such as the U.S.A., the U.A.R., Sudan, Uganda etc. The following are the approximate c.i.f. values of cotton imported from different countries:

U.A.R.	Rs. 1,666 per bale.
Sudan	Rs. 1,364 per bale.
U.S.A.	Rs. 961 per bale.
East Africa	Rs. 981 per bale.

Completion of Blast Furnace No. 4 of Rourkela

***100. Shri R. Barua:** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether the erection work of blast furnace No. 4 of Rourkela Steel Works has been completed within the scheduled time;

(b) whether the assistance of any Indian concern in the erection work was sought for and made available; and

(c) the extent to which this new addition will increase the production of the ingot steel?

The Minister of State in the Ministry of Steel Mines and Metals (Shri P. C. Sethi): (a) and (b). There has been some delay in the construction of Blast Furnace No. 4 at Rourkela because of the failure on the part of an Indian contractor who had been entrusted with a part of the work.

(c) The new addition will increase ingot steel production ultimately by 0.8 million tonne per annum.

रेल किरायों की दरों में अन्तर

101. श्री रामसेवक यादव :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री रवि राय :
श्री मधु लिमये :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन स्थानों पर जहां छोटी तथा बड़ी रेलवे लाइनें साथ-साथ चलती हैं, किराये की दरों में अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन दोनों लाइनों पर यात्रा के लिये टिकटों की व्यवस्था इस तरह की है कि इनमें से केवल एक ही लाइन पर यात्रा की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस अन्तर को दूर करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां छोटी और बड़ी लाइनें समानान्तर चलती हों और उनके किरायों में अन्तर हो । लेकिन पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर न्यू जलपाईगुड़ी और

सिलीगुड़ी टाउन/सिलीगुड़ी जंक्शन के बीच एक छोटी लाइन और एक मीटर लाइन साथ-साथ चलती हैं और उन दोनों के किराये में अन्तर है ।

(ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की बड़ी और मीटर लाइन खण्डों की अपेक्षा दार्जिलिंग हिमालयन खण्ड पर अधिक ऊंची दर पर किराया लिया जाता है । छोटी लाइन खण्ड को सिलीगुड़ी जंक्शन से न्यू जलपाईगुड़ी तक बढ़ा दिये जाने के फलस्वरूप दार्जिलिंग-हिमालयन खण्ड पर अधिक दर पर लिया जाने वाला किराया इस बढ़े हुए छोटी लाइन खण्ड पर भी लागू कर दिया गया ।

(ग) जो यात्री छोटी या मीटर लाइन से यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें उनकी इच्छानुसार छोटी या मीटर लाइन के अलग-अलग टिकट जारी किये जाते हैं ।

(घ) जी हां ।

कपड़े के मूल्य

***102. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री बलराज मधोक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री मोहन स्वरूप :
डा० रानेन सेन :
श्री प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्रनाथ :
श्री राणे :
श्री सात्य बसु :
श्री जनार्दनन :
श्री सतीशन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह से कन्ट्रोल वाले कपड़े के मूल्य में 4½ प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या जनता को कान्ट्रोल की दरों पर कपड़ा उपलब्ध कराने की दृष्टि से कोई और कदम उठाया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). 19 अप्रैल, 1967 से कन्ट्रोल वाले कपड़े के मिल से चलते समय के मूल्यों में वृद्धि की गयी है, जिसमें रुई की लागत और मजदूरी में वृद्धि का, जो अक्तूबर 1966 में पहिले मूल्य संशोधन करने के बाद हुई है, ध्यान रखा गया है ।

देश भर में छपे हुए दामों पर कान्ट्रोल वाले कपड़ों की उपलब्धि पर सतत निगरानी रखी जाती है । यह सुनिश्चित करने के लिये कि कन्ट्रोल वाला कपड़ा उपभोक्ताओं को नियत दामों पर मिले, राज्य सरकारों के सहयोग से आवश्यक प्रवर्तन व्यवस्था की गई है । अपराधी व्यापारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है । कपड़ा बाजारों की समय-समय पर जांच तथा निरीक्षण किये जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ताओं को कन्ट्रोल वाला कपड़ा नियत दामों पर ही प्राप्त होता है । कुछ अधिक बारीक कपड़े को छोड़कर, जिसके लिये आयतित रुई की जरूरत पड़ती है, कन्ट्रोल वाले कपड़े की कमी के बारे में कुल मिलाकर कोई शिकायत नहीं है ।